बैंकों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है:

- **अवमानक परिसंपत्तियां(Sub-standard Assets):** इन परिसंपत्तियों को 12 महीने या इससे कम की अवधि के लिए NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **संदिग्ध परिसंपत्तियां(Doubtful Assets):** ये परिसंपत्तियां 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए NPA बनी हुई होती हैं।
- **हानि वाली परिसंपत्तियां(Loss Assets):** हानि वाली परिसंपत्तियां वह होती है जिनमें बैंक द्वारा अथवा आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा या RBI निरीक्षण द्वारा हानि की पहचान की गई है लेकिन यह राशि पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।

RBI के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPAs) वर्ष 2014 के बाद से दोगुनी हो गई है। लेकिन यह वित्त वर्ष 2019 में 9.5 ट्रिलियन से घटकर 30.9.2021 तक लगभग 8 ट्रिलियन हो गई है। NPA के मुद्दे को हल करने के लिए, भारत सरकार ने चार प्रमुख क्षेत्रों (4R's) में हस्तक्षेप की शुरुआत की है:

1. **पहचान (Recognition):** NPA या छिपे हुए दबाव की पहचान:

- पारदर्शी तरीके से NPA की पहचान करने के लिए वर्ष 2015 में बड़े पैमाने पर परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (Asset Quality Review) शुरू की गई थी।
- एक उधारकर्ता में संकट के शुरुआती संकेतों की पहचान करने के लिए वृहद ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (CRILC) के साथ एक बड़ा क्रेडिट डेटाबेस बनाया गया है।
- कमजोर वित्तीय तंत्र वाले बैंकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए RBI द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचा तैयार किया गया है।

2. **बैंकों का पुनर्पूजीकरण (Recapitalization of Banks):**

- मिशन इंद्रधनुष को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बजटीय आवंटन और पुनर्पूजीकरण बांड के माध्यम से राज्य संचालित बैंकों में अधिक पूंजी डालना था ताकि वे पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा कर सकें। तब से, बैंकों को बेसल III मानदंडों को पूरा करने के लिए लगभग ₹3 ट्रिलियन का निवेश किया गया है। इस राशि में वित्त वर्ष 2020 में अतिरिक्त ₹ 70,000 करोड़ का निवेश भी शामिल है।
- राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) या बैड बैंक को वर्ष 2021 में शुरू किया गया है। NARCL के तहत विभिन्न चरणों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मूल्य के फंसे कर्ज की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के तहत, 15 प्रतिशत नकद और 85 प्रतिशत प्रतिभूति प्राप्ति (SRs) के माध्यम से इन परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने NARCL द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति (SRs) को वापस करने के लिए 5 वर्ष के लिए 30,600 करोड़ रुपये की गारंटी दी।

3. **दिवालियेपन का समाधान (Resolution of Insolvency):**

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता(IBC): IBC को वर्ष 2016 में दिवालिया खतों के लिए 180 दिनों की समयबद्ध वसूली प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- प्रोजेक्ट सशक्त: इसका उद्देश्य उच्च प्राथमिकता पर अधिक मूल्य वाली परिसंपत्तियों का समाधान करना है। परियोजना के तहत, ₹50 करोड़ तक के बैड लोन का प्रबंधन बैंक स्तर पर किया जाएगा। ₹50-500 करोड़ के बैड लोन के लिए, बैंक एक अंतर-ऋणदाता समझौता करेगा। साथ ही, इसमें ₹500 करोड़ से ऊपर के ऋणों के लिए एक स्वतंत्र परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) सृजित करना प्रस्तावित है।